(ii) G.S.R. 1259 published in Gazette of India dated the 24th November, 1973 together with an explanatory memorandum.

(iii) G.S.R. 505(E) published in Gazette of India dated the 26th November, 1973 together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See* No. LT-5929/73].

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 501(E) published in Gazette of India dated the 20th November, 1973 issued under the Central Excise Rules, 1944 together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See* No. LT-5930/73].

(3) A copy of Notification No. F. 5(11)-W&M/73 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 6th December, 1973 regarding floatation of market loans by the Central Government. [*Placed in Library. See* No. LT-5931/73].

(4) A copy of the National Savings Certificates (Fifth Issue) (Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 506(E) in Gazette of India dated the 26th November, 1973, under sub-section (3) of section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 [*Placed in Library. See* No. LT-5932/73].

12.30 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL:—Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Water (Prevention and Control of Pollution) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th November, 1973."

WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Water (Prevention and Control of Pollution) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

ASSENT TO BILL

SECRETARY-GENERAL: Sir, I also lay on the Table the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1973, passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 30th November, 1973.

12.32 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 10th December, 1973, will consist of :

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of :

(i) The National Cooperative Development Corporation (Second Amendment) Bill, 1973.

(ii) The Konkan Passenger Ships (Acquisition) Bill, 1973.

[Shri K. Raghu Ramaiah]

(3) Discussion and voting on :

(i) Demands for Excess Grants (General) for 1971-72.

(ii) Supplementary Demands for Grants (General) for 1973-74.

(4) Consideration of a motion for reference of the Constitution (Thirty-Second Amendment) Bill, 1973 to a Joint Committee.

(5) Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1973-74.

(6) Consideration and passing of the Income-Tax (Amendment) Bill, 1973.

(7) Consideration and passing of the following Bills as passed by Rajya Sabha :

(i) The Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1973.

(ii) The Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973.

(8) Discussion on the 22nd Annual Report of the Union Public Service Commission.

(9) Discussion on the Motion regarding working of the Food Corporation of India.

MR. SPEAKER: The notices which I receive are on the increase. So many members have started giving it. I would only request you to plainly refer to the factual matter in a minute or so and not make speeches.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Today it has been found in the Bulletin that under rule 377 members have raised such and such matter.

MR. SPEAKER: The other day one from Shri Samar Guha got published in the agenda. It was a mistake perhaps.

SHRI S. M. BANERJEE: I am not talking of that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): It may be that it is my fault that I gave you a wrong impression because in the past 377 notices used to be pubished in the list of business more frequently.

MR. SPEAKER: This is very difficult.

श्री मधु लिमये (बांका) : हमेशा रखा जाता था। अगर उसी दिन दिया जाता था तब नहीं आता था। लेकिन अगर दो तीन दिन पहले से दिया जाता तो आ जाता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एजेन्डा पेपर पर आ जाया करे तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह नहीं होगा। मुझे गलत रास्ते पर न डालिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब तो आप इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसीडेंट हो गये यूनिवर्सल अब तो कीजिये।

MR. SPEAKER: Do not try to tickle me. I am not sitting here as President of the IPU.

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिस रोज मैं पी० ए० सी० का चेयरमैन बना था आप ने उसी दिन बताया था, हम ने आज बता दिया।

We are proud of it.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मूरैना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा संसद कार्य मंत्री से कुछ मामलों पर बहस की मांग करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 8 किलो अनाज प्रति यूनिट देते हैं मैं उस का विरोध नहीं करता हूं, परन्तु चाहता हूं कि सभी प्रान्तों में इतना अनाज मिले। आज कहीं डेढ़ किलो और कहीं दो किलो प्रति यूनिट अनाज मिलता है, और केरल में साढ़े पांच छटांक मिल रहा है। तो इस पर चर्चा कराइये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइबस कमिश्नर की रिपोर्ट पर 8 घंटे की चर्चा कार्य समिति ने तय की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर कब चर्चा होगी ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल जो है पिछली लोक सभा में लैप्स हो गया था आप पुनः कब लाने वाले हैं? साथ ही साथ यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर छात्रों की हड़ताल चल रही है। उस पर कब चर्चा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने एक बात लिखी और दो उस के साथ जोड़ दी यह ठीक नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): अध्यक्ष जी, गत 30 नवम्बर को हम लोगों ने इसी सदन में आल इंडिया मेकेनिकल स्टाफ़ ऐसोसियेशन और सिगनल और टेली कम्युनिकेशल के जो लोग वर्कटू रूल का आन्दोलन चला रहे हैं उस पर बहस की थी और हम लोगों ने उम्मीद की थी कि उस के बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है । सैकड़ों ट्रेन्स कैंसिल हो चुकी हैं गाड़ियां विलम्ब से आ रही हैं कोई सुधार नहीं हुआ है । नतीजा यह है कि हवाई जहाज तो बन्द ही हैं रेलों के बन्द होने का भी खतरा है । मैं ने अखबार में पढ़ा है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप लम्बा चौड़ा भाषण क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बता रहा हूं कि रेल में इन वजूहात से कठिनाई पैदा हो गई है । यात्रियों को चलने में और सामान पहुंचाने में कठिनाई हो रही है । आज उन के सभापति ने भी कहा है कि अगर वेस्टर्न रेलवे यूनियन के लोगों की मांग नहीं मानी गई तो 48 घंटे के अन्दर रेल में हड़ताल हो सकती है । इस का नोटिस दिया है आल इंडिया रनिंग स्टाफ़ ऐसोसियेशन की तरफ़ से । तो स्थिति गम्भीर हो रही है । सरकार इसमें हस्तक्षेप करने के बजाय चुपचाप बैठी हुई है शायद इंतजार कर रही है कि पूरी हड़ताल होगी तब कुछ करेगी । तो जो लोग नियम के मुताबिक काम कर रहे हैं--आल इंडिया सिग्नेल और टैलीकम्युनिकेशन स्टाफ़ ऐसोसियेशन आल इंडिया, रेलवे मेकेनिकल स्टाफ़ ऐसोसियेशन और आल-इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ़ ऐसोसियेशन --इन तीनों संस्थाओं से मंत्री जी बात कर के कोई रास्ता निकालें। नहीं तो लगता है कि हड़ताल अवश्यम्भावी है । इसलिये मेरी मांग है कि सरकार तुरन्त बातचीत करे।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो लम्बा चौड़ा भाषण कर दिया ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय , आप हम लोगों पर इनायत फ़रमाते हैं जिस की वजह से प्रश्नों को उठाने का मौका मिलता है । लेकिन पिछले 10 , 15 दिनों में जो सवाल उठाये गये उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। बढ़ैया, मुंगेर जिला बिहार में एक ढाढ़ी जाति के हरिजन को जिन्दा जलाया गया था लेकिन उस बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं आया ।

इंडियन काटन मिल्स फ़ैडरेशन जो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर हुई थी 10 साल तक उन्होंने इन्कम टैक्स की चोरी की। यह मामला भी आप के सामने लाया गया। वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, उस का भी खुलासा होना चाहिए। बड़ी शक्तिशाली संस्था है।

तीसरी बात यह है कि कि हमारी कोयाली और बेरौनी रिफ़ाइनरीज में 7 प्रतिशत, बल्कि

(श्री मधु लिमये)

उस से भी अधिक, क्रूड आयल गायब हो जाता है, जब कि इन्डोनेशिया जैसे अविकसित देश में 3 प्रतिशत लौस है और रूस और दूसरे देशों में एक और डेढ़ प्रतिशत तक लौस है इस विषय में स्वयं रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और माननीय बरूआ जी के सामने बातचीत हुई थी।

नया मामला केवल एक ही उठाना चाहता हूं और वह यह है कि आज सभी समाचार-पत्रों में खबर आयी है कि रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात कारखाने तकरीबन बन्द होने की स्थिति में हैं। कोक ओवन प्लांट बन्द हो चुके हैं, और इधर कोल अथोरिटी, श्री कुमारमंगलम कहते हैं कि नवम्बर में अक्तूबर की तुलना में 15 प्रतिशत कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और केवल रेल वैगनों की कमी की वजह से, रेल मंत्रालय के चलते हमारे तीन पब्लिक सैक्टर के इस्पात कारखाने अगर बन्द होते हैं तो बड़ा गंभीर मामला है। वास्तव में हम लोगों को इस पर ऐडजर्नमेंट मोशन देना चाहिये था और आप को स्वीकार करना चाहिये। लेकिन कम से कम इसका खुलासा तो हो।

MR SPEAKER: About the shortage of coal so far as these steel plants are concerned, 1 very much expect a statement to be made on the very first day of next week.

SHRI S. M. BANERJEE: I would like to mention only two points, because on the third point, I am sure, the hon. Minister of Civil Aviation is making a statement. The first point is this. You will be surprised to hear that even after the assurance of the hon. Deputy Minister in the Ministry of Defence in this House that the services of 8,000 MES—Military Engineer Services—employees who were doing a very important job in the defence industries will not be terminated unless alternative jobs are found, I am told today by the various unions throughout the country that their number is not 8,000 but 11,000 and that the services of these trained personnel who have worked for three to five years in the MES in the defence department are being trminated. I would request the hon. Defence Minister to make a statement to allay the fears in the minds of 11,000 employees that their services are going to be terminated. I do not wish to threaten the Government but I want to mention here that in case these 11,000 Defence employees were retrenched on 1st January 1974 the Federation will be bound to take a strike notice and go on strike because unemployment is so great.

Secondly, we want a discussion on the Pay Commission Report. We were told in the House that everything had been done and that the Minister had increased the salary in certain cases. You will be surprised that 80 per cent of the Central Government employees did not get a pay rise in December; only 20 per cent got. Even the pay scales recommended by the Pay Commission have not been implemented. We want you to allow a discussion on the Pay Commission Report so that the hollow assurances gives by the Government might be exposed before the people in general and the Central Government employees in particular.

MR. SPEAKER: I request the Members to mention only one or two points.

SHRI S. M. BANERJEE: Lastly, you should ask the Minister for Scientific Research Mr. Subramnaiam to make a statement on the proposed closure or virtual closure of Sri Ram Institute in Delhi. Today they met the Prime Minister and she assured that she would intervene in the matter. Why is the Government unable to make a statement in this House? Because of the fear of Mr. Charat Ram and Mr. Bharat Ram? Their father is dead; they used to be afraid of Mr. Sri Ram. Let the Minister say something.

MR. SPEAKER: Please do not make such observations; it is unfair. It is not in good taste to make a reference to

them and say their father is dtad, etc. etc. howsoever you may differ from them.

SHRI P. R. SHENOY (Udipi): The cashew industry which is labour-intensive, foreign exchange earning, small-scale industry is facing a serious crisis in Mangalore due to non-availability of imported raw cashew. The import of raw cashew is canalised through the Cashew Corporation of India and the Cashew Corporation of India is not importing enough raw cashew from East African countries, nor is it making equitable distribution of cashew imported by it. Mangalore is the birth place of cashew industry but discrimination is made against Mangalore in the distribution of imported raw cashew by the Cashew Corporation. I request the Commerce Ministry to see that immediately 5,000 tonnes of raw cashew are imported from East African countries so that the workers are not thrown out of employment. Cashew industry earns a foreign exchange of about Rs. 70 crores. It is now facing severe competition from East African countries and once you lose foreign markets it is difficult to recapture it. I request the Commerce Ministry to pull up the Cashew Corporation of India and see that sufficient quantities of cashew is supplied to manufacturers in Mangalore immediately so that the units may not be closed down.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): अध्यक्ष महोदय देश के कुछ प्रदेशों में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, इस दृष्टि से चुनाव कानून में संशोधन आवश्यक है इस बारे में एक विधेयक पार्लियामेंट के सामने आया था उसे ज्वायट सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था जिस की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है लेकिन वह विधेयक सदन के सामने नहीं लाया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि उस विधेयक को लाने में देर होने का क्या कारण है।

आज कल उत्तरप्रदेश में प्रतिदिन या तो किसी कारखाने की नींव रखी जा रही है या किसी बहुत का उदघाटन किया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के विकास का समर्थन करते हैं, लेकिन चुनाव के समय जब विकास की याद आती है तो ऐसा लगता है कि यह शासन तंत्र का दुरुपोंयोग किया जा रहा है मैं एक गम्भीर मामला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं :

"Nainital, November 22:

The Union Government has agreed to a proposal to link the hill region of Kumaon with the BG railway line, according to the U.P. Finance Minister, Shri Narain Dutt Tiwari."

उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री नेनीताल से यह ऐलान करते हैं कि कुमाऊ को जोड़ने वाली छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदली जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फ़ैसला कब किया गया और यह फ़ैसला किस ने किया। मैं ने 1972–73 का रेलवे बजट देखा है। डिमांडज फ़ार ग्रान्टस पर जो चर्चा हुई है, मैंने उस की भी छान बीन की है। उस से पता चलता है कि अभी तक रेल मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई फ़ैसला नहीं किया है—और अगर फ़ैसला किया है, तो रेल मत्री की तरफ़ से उस का ऐलान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फ़िनांस मिनिस्टर रेलें कब से चलाने लगे? चूंकि कुमाऊं की रेलवे लाइन उन के चुनाव-क्षेत्र में आती है, और उत्तर प्रदेश में आती है, इस लिए उन्होंने इस बारे में ऐलान कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव में सब कुछ चल जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा मत कहिये, क्योंकि आप को देखना है कि जो संसद के अधिकार-क्षेत्र की बात है, वह संसद के अधिकार-क्षेत्र में ही रहनी चाहिए। अगर रेल मंत्री महोदय ने यह फ़ैसला किया है कि उस छोटी लाईन को

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी)

ब्राडगेज में बदला जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस की घोषणा इस सदन में, रेल मंत्री के द्वारा, होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री के द्वारा नहीं। (व्यवधान) यह अखबार में निकला है; क्या यह गलत है? क्या श्री तिवारी ने इसका खंडन किया है! अगर रेल मंत्री इस का खंडन कर दें, तो मैं मान लूंगा। (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि इस तरह शासन-तंत्र का दुरुपयोग ठीक नहीं है। विकास एक अलग बात है। श्री राज बहादुर मेरी बात का समथन करेंगे कि श्री सुखाड़िया ने अपने चुनाव के समय एक नाला बनवाया था और उस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि यह इस प्रैक्टिस है।

संसदीय कार्य तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): मुझे इस की कोई इत्तिला नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अब वह इन्कार कर रहे हैं! वह अपने आप को अनजान बता रहे हैं। (व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि इस तरह के निर्णय की घोषणा संसद में होनी चाहिए, सम्बन्धित मंत्री के द्वारा होनी चाहिए, किसी प्रदेश के मंत्री के द्वारा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इलेक्शन ला में एमेंडमेंट करने वाला बिल इसी सत्र में लायें और इसी सत्र में पास करायें, जिस से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे या नहीं, लेकिन उस दिशा में थोड़ा सा कदम जरूर बढ़ाया जा सकेगा।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, we are at a loss to understand what could be the reasons for the Protocol attached to the trade agreement between USSR and India not having been released till now. In contrast, we find that the Protocol on Economic, Technical and Scientific Cooperation between the Governments of India and Czechoslovakia has already been released, although this agreement was concluded later. This makes our position a little difficult because we are not able to understand the full import or significance of the agreement reached between these two countries. Very soon we are going to discuss this very matter either in the form of a debate on the international situation or the agreement reached between USSR and India. So, we would like to know when does the Government propose to release this protocol and what were the reasons because of which the Government has withheld this protocol from the House and the country.

12.50 hrs.

STATEMENT *RE.* DELAYS IN LAYING OF STATUTORY ORDERS.

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra): On the 15th and 22nd November, 1973, when the Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) was laying certain 'Orders' on the Table of the House, some hon. Members expressed concern over the inordinate delay in laying of 'Orders', which ranged from one to two years. It was, *inter alia*, suggested by one of the Hon. Members during the course of discussion that the Committee on Subordinate Legislation of this House had not been vigilant enough to take notice of these delays.

I would crave the indulgence of the House to correct this impression. In their successive Reports, the Committee on Subordinate Legislation have been deprecating delays in laying of 'Orders'. Each 'Order' laid on the Table of the House is *suo motu* examined by the Committee to see whether there had been a delay beyond the period of 15 days prescribed by the Committee in its laying. In cases of delays exceeding six months, the Committee have been calling Secretaries/Joint Secretaries of the Ministries to give an explanation for delay.